छोटे तथा मझौले समाचार पत्रों को उपलब्ध सुविधाओं तथा आधुनिकीकरण के लिए ऋणों की व्यवस्था होने से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित छोटे तथा मझौले समाचारपत्रों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

ईदे मिलादुन्नबी को छुट्टी

1542. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्व प्रधान मंत्री ने 1990 में ईदे मिलादुन्नबी को राजपत्रित छुट्टी के रूप में मनाये जाने के बारे में घोषणा की थी और उस वर्ष उस दिन छुट्टी मनायी गई थी; और

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके बाद इस छुट्टी को समाप्त कर दिया गया; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) जी, हां।

(ख) गत वर्ष की तरह इस त्यौहार पर छुट्टी घोषित की जा रही है।

समाचारपत्रों की भाषावार संख्या

1543. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल**: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1990 में प्रकाशित समाचार-पत्रों की भाषावार संख्या कितनी है; और

(ख) प्रत्येक समाचारपत्र की प्रसार संख्या कितनी-कितनी है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) वर्ष 1989 में प्रकाशित समाचार पत्रों की भाषावार अद्यतन उपलब्ध संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **देखिए** परिशिष्ट CLX, अनुबंध सं० 58)

(ख) प्रत्येक समाचार-पत्र की प्रसार संख्या देना संभव नहीं है क्योंकि सभी समाचार पत्र अपना वार्षिक विवरण भारत के समाचार पत्रों के कार्यालय को नहीं भेजते।

भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठने वाले इंजीनियर

1544. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च प्रभाव को देखते हुए कितने इंजीनियर इस सेवा में प्रवेश कर चुके हैं और कितने इंजीनियर भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठे; और

(ख) क्या सरकार देश के विकास में इंजीनियरों की तकनीकी दक्षता का इष्टतम उपयोग करने के उद्देश्य से उन्हें अन्य सेवाओं में जाने से रोकने के लिए उपाय करने का विचार रखती है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) सूचना निम्न प्रकार है:-

सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले इंजीनियरों की संख्या		भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त इंजीनियरों की संख्या
1988	1853	27
1989	1917	44
1990	2172	51

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में किसी भी विषय के स्नातक

भाग ले सकते हैं और यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के हित में नहीं होगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा को किसी को एक विशेष विषय वालों के लिए सीमित कर दिया जाए क्योंकि विविध शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले अधिकारियों के आने से इस सेवा की गुणवत्ता बढ़ती है।

Setting up separation Plants for Isotopes

1545. SHRI KAMAL MORARKA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any plan to set up some separation plants for isotopes and heavy water in the country in near future;

(b) if so, what are the details regaridng their locations and the availability of raw materials and production; and

(c) whether these plants will run under Government or be a joint venture with the State Governments?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) Bhabha Atomic Research Centre (BARC) has a proposal to set up during the Eighth Plan period a Pilot Plant for enrichment of Boron-10 Isotope from Boric Acid.

The need for setting up additional Heavy Water Plants would depend on the size of the Nuclear Power Programme and the financial resources that would be made available in the future Five Year Plans.

(b) The boron plant will be located within BARC campus. The main raw material for this plant is Boric Acid, which is being produced in the country. The other raw materials are common chemicals and are all available in the country.

Suitable sites for location of additional Heavy Water Plant have been identified based on technical considerations. Final decision on any of them has not yet been taken as the size of Five Year Plan is yet to be finalised.

(c) The boron plant will be run under the Department of Atomic Energy.

Regarding Heavy Water Plants the matter will be decided at the appropriate time.

CSD Depot in South Block, New Delhi

1546. SHRI J. P. JAVALI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that C.S.D. Depots in the South Block, New Delhi are not being properly catered to, leading to lack of quality goods for jawans and Army personnel;

(b) what steps Government propose to take to change the existing system of excessively centralised control from Bombay over the functioning of C.S.D. dipots all over the country;

(c) what alternative arrangements has been mooted by his ministry to make the Canteen Stores Depots decentralised and modernised;

(d) whether it is a fact that depot managers are left without any potential for initiative in trying to meet demand of local defence service personnel; and

(e) the measures being taken to rectify such faults in existing management of C.S.D.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) There is no C.S.D. Depot/Unit Run Canteen in the South Block. The AHQ Canteen (URC) in Q Block, New Delhi is well stocked and there has been no complaint regarding the quality of goods offered for purchase